गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 274
दि. 05.02.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'विपक्ष की महिला सांसदों ने घेर ली पीएम मोदी की कुर्सी, नहीं दे पाए भाषण', लोकसभा में हंगामे पर भाजपा का दावा

लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था. हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो सका. अब बीजेपी ने इसे लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में शाम पांच बजे बोलने वाले थे. पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देना था. लेकिन जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी. पीठासीन संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी और पीएम मोदी का संबोधन टल गया.

इसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं, विपक्ष के लोग वहां तक चढ़ गए थे. उन्होंने कहा कि विपक्ष की महिला सदस्यों ने पीएम की चेयर का घेराव किया और उनकी मंशा प्रधानमंत्री पर हमले की थी.

मनोज तिवारी ने विपक्षी सदस्यों पर सदन में बवाल करने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की महिला सांसदों को हमारे वरिष्ठ मंत्री ने समझाया और वापस जाने का निवेदन करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नहीं आ सकते. लेकिन महिला सांसद सुनने को तैयार नहीं थीं. मनोज तिवारी ने दावा किया कि विपक्ष के सांसद मारपीट करने वाले हाव-भाव के साथ आए थे.

वहीं, सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के घटक चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद राजेश वर्मा ने भी लोकसभा में हुए घटनाक्रम को लेकर बयान दिया है. राजेश वर्मा ने कहा है कि विपक्ष के कुछ सांसद हाथों में बैनर-पोस्टर लिए ऐसे दौड़ रहे थे, जैसे वह सड़क पर हों. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों ने ऐसा माहौल बना दिया, कि हम हाथापाई पर उतर जाएं.

एलजेपीआर सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्ष की महिला सांसद ट्रेजरी बेंच की तरफ बढ़ीं. उन्होंने कहा कि विपक्षी महिला सांसद जहां पीएम बैठते हैं, उससे दो कतार पीछे तक पहुंच गईं और निशिकांत दुबे की तरफ बढ़ने लगीं. अश्विनी वैष्णव और अन्य मंत्री उन्हें समझाने लगे, लेकिन वो महिला सांसद आगे बढ़ रही थीं. बाद में कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने सभी से वापस आने को कहा.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जैसा मैंने कहा, पीएम मोदी संसद में नहीं आएंगे. राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते.

कांग्रेस की महिला सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि जोतिमणि, गनीबेन ठाकुर और हम निशिकांत दुबे की ओर बढ़े. प्रधानमंत्री तब सदन में नहीं थे. हमने निशिकांत दुबे से कहा कि निशिकांत क्या बोल रहे थे महिलाओं को लेकर, इधर आओ इधर आओ. इस पर निशिकांत वहां से जाने लगे. हमने ये कहा कि भाग रहा है, भाग रहा है. इस दौरान एनडीए की महिला सांसद भी उधर से आने लगी थीं. बाद में टेंशन डिफ्यूज किया गया और हम सभी वापस लौट आए. हंगामे के कारण पीठासीन संध्या राय ने जब सदन की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी, विपक्षी दलों के नेता बैनर-पोस्टर लेकर चेयर के सामने पहुंच गए. विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और ट्रेजरी बेंच की ओर पहुंच गए. अनुराग ठाकुर, किरेन रिजिजू और अश्विनी वैष्णव ने विपक्षी नेताओं से बात करनी शुरू की. दीपेंद्र हुड्डा और जोतिमणि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर पहुंचे. इस दौरान इनके हाथ में पोस्टर भी था.

सीता मइया के दिव्य चरित का ज्ञान करायेगी 'वैदेही आर्ट गैलरी' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ, (जीएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीअयोध्या धाम में माता सीता के जीवन-चरित पर केंद्रित 'वैदेही आर्ट गैलरी' की स्थापना के निर्देश दिए हैं। बुधवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक में उन्होंने कहा कि सीता मइया भारतीय संस्कृति, मयार्दा और नैतिक आदर्शों की अनुपम प्रेरणा हैं, और नई पीढ़ी को उनके उज्ज्वल चरित्र से गहराई से परिचित कराना समय की आवश्यकता है।

आर्ट गैलरी की परिकल्पना साझा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह अत्याधुनिक गैलरी

केवल एक कला-संग्रहालय न होकर, सीता माता के जीवन, त्याग, करुणा, मयार्दा, धैर्य और शक्ति का आधुनिक तकनीक के माध्यम से पुनर्पाठ प्रस्तुत करने वाली एक जीवंत सांस्कृतिक अनुभव-स्थली होनी चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिया कि इस गैलरी की कथा-वस्तु, डिजाइन, विजुअल भाषा, कला और तकनीक सहित सभी आयाम इस भावना को प्रकट करे कि हम एक दिव्य विरासत का पुनर्पाठ कर रहे हैं, जिसे नई पीढ़ी के सामने प्रेरणास्रोत के रूप में स्थापित किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैदेही आर्ट गैलरी की मूल भावना यही हो कि आगंतुक सीता माता के जीवन-संदेश को केवल देखें नहीं, बल्कि उसे अनुभव करें, समझें और आत्मसात करें।

अयोध्या विकास प्राधिकरण के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निकट वशिष्ठ भवन परिसर में विकसित की जा सकती, जहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि इस गैलरी का विकास अयोध्या के वैश्विक सांस्कृतिक नगर के रूप में उभरने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण चरण होगा। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि मिथिला की संस्कृति, लोकपरंपरा और कला के विविध आयामों को गैलरी में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।

संक्षिप्त समाचार

शुक्रवार को पंचूर पहुंच सकते हैं योगी आदित्यनाथ

ऋषिकेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक निजी समारोह में शामिल होने के लिए शुक्रवार को अपने गांव पंचूर पहुंच सकते हैं। जनता इंटर कॉलेज यमकेश्वर में नवनिर्मित कक्षा कक्षों के लोकार्पण समारोह में भी शामिल हो सकते हैं। जनता इंटर कॉलेज चमकोट खाल में योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 9 की पढ़ाई की थी।पंचूर गांव में जन्मे योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय पंचूर, कक्षा 6 से 8 तक जूनियर बिथ्याणी, कक्षा 10 खाड़ी हाई स्कूल नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल, कक्षा 11 एवं 12 भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश जबकि स्नातक की पढ़ाई कोटद्वार महाविद्यालय से की थी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में श्री जतिन ठक्कर को शपथ दिलाई

गांधीनगर, 04 फरवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को गांधीनगर में गुजरात विद्युत नियामक आयोग (जीईआरसी-जर्क) के सदस्य के रुप में नियुक्त किए गए श्री जतिन ठक्कर को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर जर्क के अध्यक्ष श्री पंकज जोषी, मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री राजेंद्र सरीन और विद्युत नियामक आयोग के सदस्यों सहित वरिष्ठ सचिव और अधिकारी मौजूद रहे।

सीएम योगी का निर्देश, लंबित आवास मामलों के निस्तारण हेतु 'एकमुश्त समाधान योजना' लागू करें

लखनऊ, (जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक में लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के लिए एक नई 'एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2026)' लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित देयों और विवादित मामलों के कारण न केवल योजनाओं की प्रगति प्रभावित होती है, बल्कि आम नागरिकों को भी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था लागू करना है, जिसमें समाधान तेज, पारदर्शी और सभी के लिए व्यावहारिक हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की किसी भी योजना में लंबित भुगतान या विवादित आवंटन राज्य की विकास गति को धीमा करते हैं। इसलिए आवास विभाग को ऐसी समाधान-प्रधान व्यवस्था लागू करनी चाहिए, जिससे विभाग को आवश्यक राजस्व प्राप्त हो और आवंटियों को भी राहत मिले। उन्होंने कहा कि यह योजना जन-केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें हर वास्तविक आवंटी को स्पष्ट और सरल विकल्प उपलब्ध हों। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020 में लागू की गई ओटीएस-2020 योजना से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण हुआ था, लेकिन कोविड-19 के कारण कई आवंटी अंतिम भुगतान नहीं कर पाए। विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में प्रदेश के विभिन्न आवासीय और

व्यावसायिक परिसरों में मौजूद ऐसे सभी डिफॉल्ट मामलों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओटीएस-2026 योजना को अधिक व्यावहारिक और लाभकारी स्वरूप दिया जाए। एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को देयों पर उपयुक्त छूट दी जाए। साथ ही, किस्तों में भुगतान की सुविधा हो। उन्होंने कहा कि योजना के प्रावधानों को अंतिम रूप देते समय यह ध्यान रहे कि योजना के मूल में आम आदमी को राहत देने का ही भाव निहित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विभाग द्वारा प्रत्येक आवेदन का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजना लागू होने से हजारों आवंटियों को राहत मिलेगी और विभाग को राजस्व भी प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की विशेष व्यवस्था की जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे अवगत हो सकें। उन्होंने कहा, 'एकमुश्त समाधान योजना' के बारे में आम जनता के बीच सक्रिय रूप से जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि सभी पात्र लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि योजना की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने मणिपुर के नवनियुक्त मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ लेने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज श्री युमनाम खेमचंद सिंह जी को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने श्रीमती नेमचा किपगेन जी और श्री लोसी दिखो जी को राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर अपनी शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने श्री कोंथौजम गोविंदास सिंह जी और श्री खुराइजम लोकेन सिंह जी को मणिपुर सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी।

नए नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए, श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वे मणिपुर के भाइयों और बहनों के लिए विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने की दिशा में पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखाः

श्री युमनाम खेमचंद सिंह जी को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने

'नो-कम्प्रोमाइज', 'हम ट्रंप के हटने का इंतजार करेंगे', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर जब रूबियो से बोले थे अजित डोभाल

(जीएनएस)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी भले ही भारत के साथ हुए व्यापार समझौते को "अमेरिकी जनता की बड़ी जीत" बताकर पेश कर रहे हों, लेकिन एक नई रिपोर्ट इन दावों की परतें खोलती नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने ट्रंप प्रशासन के आक्रामक रवैये के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया था और जरूरत पड़ने पर उनके पूरे कार्यकाल के खत्म होने तक इंतजार करने को भी तैयार था।

डोभाल ने बोला था- धमकियों से नहीं चलेगा रिश्ता

इस पूरे घटनाक्रम की जड़ सितंबर 2025 की शुरूआत में हुई एक गोपनीय बैठक बताई जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को दो टूक शब्दों में बता दिया था

कि भारत किसी भी तरह की 'बुलिंग' स्वीकार नहीं करेगा।

डोभाल ने स्पष्ट किया कि अगर रिश्तों में तल्खी कम नहीं हुई, तो भारत 2029 तक किसी भी व्यापार समझौते का इंतजार कर सकता है।

यह बैठक ऐसे समय में हुई थी जब ट्रंप प्रशासन लगातार मोदी सरकार की आलोचना कर रहा था। उस दौरान भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत का भारी टैरिफ लगाया गया था, जो उस वक्त अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाया गया सबसे ऊंचा शुल्क माना जा रहा था।

डोभाल ने रुबियो से यह भी मांग की कि भारत के खिलाफ सार्वजनिक मंचों पर की जा रही आलोचना रोकी जाए, क्योंकि इससे द्विपक्षीय रिश्तों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है।

दिल्ली के अधिकारियों के अनुसार, इस कड़े संदेश के बाद सितंबर के अंत तक ट्रंप के रुख में कुछ नरमी दिखाई देने लगी। इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर फोन कर बधाई दी। इसे दोनों देशों के बीच जमी बर्फ के पिघलने की शुरूआती संकेत के तौर पर देखा गया।

भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव की असली शुरूआत मई 2025 में हुई, जब भारत ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान ट्रंप के युद्धविराम संबंधी दावों को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया। इसके बाद ट्रंप के करीबी सहयोगियों, खासकर पीटर नवारो, ने प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले किए। रूसी तेल की खरीद को यूक्रेन युद्ध से जोड़ते हुए इसे 'मोदी का युद्ध' तक कहा गया, जिसने हालात और बिगाड़ दिए।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस 'भारत टैक्सी' का शुभारंभ करेंगे

(जीएनएस)।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 05 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के पहले सहकारिता-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म ह्यभारत टैक्सीह्न का शुभारंभ करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन के अनुरूप यह शुभारंभ सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ करने और समावेशी, नागरिक-केंद्रित मोबिलिटी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा,।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और जमीनी स्तर पर आर्थिक भागीदारी के सशक्त माध्यम के रूप में सहकारी संस्थानों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत टैक्सी को मोबिलिटी क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसमें ड्राइवरों—जिन्हें सारथी कहा जाता है—को स्वामित्व, संचालन और मूल्य-निर्माण के केंद्र में रखा गया है, जिससे वे शोषणकारी एग्रीगेटर-आधारित मॉडलों से मुक्त हो सकें।

कार्यक्रम के दौरान सहकारिता-आधारित मोबिलिटी इकोसिस्टम में उत्कृष्ट योगदान के लिए शीर्ष छह प्रदर्शन करने वाले सारथियों को सम्मानित किया जाएगा। माननीय मंत्री इन सारथियों को शेयर प्रमाणपत्र वितरित करेंगे, जिससे ह्यसारथी ही मालिकह्न के मूल सिद्धांत को और अधिक मजबूती मिलेगी। प्रत्येक सम्मानित सारथी को ₹5

लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा तथा ₹5 लाख का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा, जो ड्राइवर कल्याण और दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा के प्रति भारत टैक्सी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस अवसर पर संचालनात्मक एकीकरण, डिजिटल सशक्तिकरण, सुरक्षा और सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख सार्वजनिक और निजी हितधारकों के साथ नौ समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाएंगे।

भारत टैक्सी बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत भारत का पहला सहकारिता-नेतृत्व वाला राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी स्थापना 6 जून 2025 को की गई थी। यह प्लेटफॉर्म शून्य-कमीशन और सर्ज-फ्री प्राइसिंग मॉडल पर कार्य करता है, जिसमें लाभ का प्रत्यक्ष वितरण ड्राइवरों को किया जाता है, जिससे यह विदेशी निवेश-आधारित एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स का एक स्वदेशी विकल्प प्रस्तुत करता है।

भारत टैक्सी सारथियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्ति बचत और समर्पित ड्राइवर सहायता प्रणाली के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। दिल्ली में सात प्रमुख स्थानों पर सहायता केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म त्वरित आपातकालीन सहायता, सत्यापित राइड डेटा प्रदान करता है और ड्राइवरों को बिना किसी अनन्य शर्त के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर काम करने की स्वतंत्रता देता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ह्बाइक दीदीह्न जैसी पहलें चलाई जा रही हैं, जिनके तहत अब तक 150 से अधिक महिला ड्राइवर भारत टैक्सी से जुड़ चुकी हैं।

अपनी स्थापना के बाद से भारत टैक्सी दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सहकारिता-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म तथा विश्व का सबसे बड़ा ड्राइवर-स्वामित्व वाला मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। अब तक लगभग चार लाख ड्राइवर भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और दस लाख से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हो चुके हैं। लगभग ₹10 करोड़ की राशि अब तक सीधे ड्राइवरों में वितरित की जा चुकी है।

आगामी वर्षों में 'भारत टैक्सी' का लक्ष्य अगले दो वर्षों के भीतर देश के सभी राज्यों और शहरों में विस्तार करना, प्रत्येक राज्य में समर्पित सहायता केंद्र स्थापित करना, ड्राइवरों की सामाजिक सुरक्षा को और सुदृढ़ करना।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

सम्पादकीय

देश में बढ़ती कैंसर की बीमारी व हमारी सामाजिक जिम्मेदारी

कैंसर की बढ़ती आहट और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी, कैंसर के इलाज में बड़ी समस्या यही है कि या तो मरीज का कैंसर ठीक ही नहीं होता या फिर इलाज के बाद इसके दोबारा वापस लौटने की संभावना बरकरार रहती है। हालांकि आज कैंसर पूरी तरह लाइलाज नहीं रहा, चिकित्सा विज्ञान द्वारा कैंसर के इलाज के लिए कई कारगर दवाएं और थैरेपी खोजी जा चुकी हैं। कैंसर की बढ़ती आहट और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी कैंसर आज वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों की असमय मृत्यु का कारण बन चुका है। यही कारण है कि कैंसर जैसे जानलेवा रोग के कारणों, उसकी समय पर पहचान और रोकथाम के प्रति लोगों को सजग करने के उद्देश्य से हर वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में पिछले दो दशकों में कैंसर रोगियों की संख्या दोगुनी हो गई है, जो न केवल स्वास्थ्य तंत्र बल्कि पूरे समाज के लिए गहरी चेतावनी है। करीब एक दशक तक चले दो वैश्विक अध्ययनों में वुछ समय पूर्व यह तथ्य भी उभरकर सामने आया कि विकसित देशों में अब कैंसर के कारण सबसे ज्यादा लोग प्राण गंवा रहे हैं। कनाडा की लावल यूनिर्वसिटी के शोधकर्ता गिल्स डेगनिस के मुताबिक वर्ष 2017 में दुनियाभर में करीब 26 लाख मौतें कैंसर के कारण हुई थी। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनियाभर में हर छह में से एक व्यक्ति की मौत अब कैंसर के कारण होती है और वर्ष 2018 में विश्वभर में 96 लाख लोगों की मृत्यु कैंसर के कारण हुई, जिनमें में से 21 लाख कैंसर रोगियों की मृत्यु पेफड़ों के कैंसर, 20 लाख की स्तन कैंसर, 18 लाख की कोलोरेक्टल कैंसर, 12 लाख की प्रोस्टेट कैंसर, 11 लाख की त्वचा कैंसर और 10 लाख कैंसर मरीजों की मृत्यु पेट के कैंसर के कारण हुई। कैंसर से मौतों का यह आंकड़ा साल-दर-साल निरंतर बढ़ रहा है और अब यह प्रतिवर्ष एक करोड़ तक पहुंच गया है। दुनियाभर में कैंसर के जितने भी मामले सामने आते हैं, उनमें से करीब 22 फीसदी तम्बावू के किसी भी रूप में सेवन के कारण ही होते हैं। यूनिर्वसिटी ऑफ वाशिगटन ने एक व्यापक अध्ययन के बाद ह्वग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजह्व नामक अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, उसके अनुसार भारत में मृत्यु के दस बड़े कारणों में से कैंसर दूसरे स्थान पर है। ह्वप्रॉस्पेक्टिव अर्बन रूरल एपीडेमियोलॉजिकह्व नामक एक अध्ययन के तहत वुछ समय पहले जब भारत सहित चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कनाडा, ब्राजील, स्वीडन, ईरान, मलेशिया, फिलीपींस, सऊदी अरब, संयुत्त अरब अमीरात, फिलिस्तीन, दक्षिण अप्रीका, अर्जेन्टीना, कोलम्बिया, चिली, तंजानिया, तुका, पोलैंड, जिम्बाब्वे इत्यादि देशों के स्वास्थ्य आंकड़ों का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि कैंसर अब पूरी दुनिया में सबसे बड़ी महामारी के रूप में उभर रहा है और अगर यह इसी गति से उभरता रहा तो आगामी वुछ दशकों या वर्षो में ही यह दुनियाभर में सबसे बड़ी प्राणघातक बीमारी बन जाएगा। प्रतिवर्ष कैंसर से पीडित लाखों मरीज मौत के मुंह में समा जाते हैं और माना जा रहा है कि कैंसर के मरीजों की संख्या एक करोड़ को पार कर चुकी है। देश में कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिता व्यत्त करते हुए नवम्बर 2019 में विज्ञान एवं तकनीक, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी संसद की स्थायी समिति ने राज्यसभा के तत्कालीन सभापति वेंवैया नायडू को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कैंसर के मामलों से निपटने और मरीजों को एक ही जगह इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देशभर में ट्रीटमेंट हब (विशिष्ट इलाज केन्द्र) बनाने की सिफारिश की थी। समिति को अत्तूबर 2019 में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जानकारी दी गई थी कि भारत में प्रतिवर्ष कैंसर के करीब सोलह लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस बीमारी से पीडित मरीजों में करीब 68 फीसदी मृत्यु दर बेहद दुखद है और मौजूदा समय में कैंसर के इलाज का देश में जो नेटवर्व है, वह इस बीमारी की भयावहता को देखते हुए बहुत छोटा और अपर्याप्त है, जिसके लिए एक ऐसे मजबूत और विशाल तंत्र की जरूरत है, जो कैंसर की दवाओं के मूल्य को नियंत्रित रख सके।

भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) एवं भारतीय व्यापार सेवा (आईटीएस) के अधिकारियों हेतु आईआईसीए द्वारा कंपनी अधिनियम, प्रतिस्पर्धा कानून एवं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

(एजेंसी)। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अंतर्गत भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (IICA) 02 से 06 फरवरी 2026 तक अपने आईएमटी मानेसर परिसर में भारतीय आर्थिक सेवा (IES) एवं भारतीय व्यापार सेवा (ITS) के 21 अधिकारियों के लिए कंपनी अधिनियम, प्रतिस्पर्धा कानून तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन IICA के महानिदेशक एवं सीईओ श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में कॉर्पोरेट कानून, प्रतिस्पर्धा कानून और दिवाला ढांचे की बढ़ती महत्ता पर जोर दिया।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत IBBI, उउक्, NFRA, ICAI, ICSI और CMA जैसे प्रमुख नियामक संस्थान कार्यरत हैं। विश्वास-आधारित नियमन (छ्र४२३-ुंरींफैं४'३ङ्घ्ल) की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम के दौरान कॉर्पोरेट मामलों के विशिष्ट क्षेत्रों पर परियोजनाएं लेने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही, उन्होंने केंद्रीय बजट 2026 की प्रमुख घोषणाओं—विशेषकर टरटए२ के समर्थन और नई ह्वकॉर्पोरेट मित्रह्व योजना—का उल्लेख किया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा IICA द्वारा अधिकारियों की भूमिकाओं और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी, ताकि उन्हें कंपनी अधिनियम, प्रतिस्पर्धा कानून, कॉर्पोरेट वित्त और दिवाला कानून जैसे प्रमुख विषयों पर संवेदनशील बनाया जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को कॉर्पोरेट मामलों के शासन से संबंधित व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना तथा उनकी नियामकीय और नीतिगत समझ को समृद्ध करना था।

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को कंपनी प्रबंधन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (उउक) की शक्तियां, कार्य एवं

जांच प्रक्रिया, अर्थशास्त्र एवं विधि निर्माण, एक विकसित होते आर्थिक कानून के रूप में क्द्ध, नियामकीय शासन, प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते, प्रभुत्व का दुरुपयोग, कॉर्पोरेट वित्त, ऋण एवं चूक, डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण, विधायी आशय, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP), नियामकीय प्रथाएं तथा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक जानकारी प्राप्त हुई। हालिया नीतिगत संशोधनों और नीति-निर्माण के अनुभवों पर भी चर्चा की गई।

कार्यक्रम में संस्थान के आंतरिक एवं बा' विशेषज्ञों ने संसाधन व्यक्तियों के रूप में सहभागिता की, जिनमें श्री सुधाकर शुक्ला (पूर्व सदस्य, क्द्बइक एवं प्रमुख, सेंटर फॉर इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, IICA), श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह (महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, IICA), श्री धनेंद्र कुमार (पूर्व अध्यक्ष, CCI), श्री जी.पी. मदान (संस्थापक, मदान लॉ ऑफिसेस), श्री समीर गांधी (पार्टनर, Axiom5 लॉ चैंबर्स), डॉ. एम.एस. साहू (पूर्व अध्यक्ष, IBBI), डॉ. ऑगस्टीन पीटर (पूर्व सदस्य, CCI), डॉ. प्यला नारायण राव (एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ कॉर्पोरेट लॉ एंड कम्पिटिशन लॉ, IICA), श्री जी.आर. भाटिया (पार्टनर, लूथरा एंड लूथरा), डॉ. नवीन सिरोही (एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, IICA), डॉ. देबज्योति राय चौधरी (प्रबंध निदेशक, NeSL), डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय (पूर्व पूर्णकालिक सदस्य, IBBI), सुश्री पूजा भार्य (इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल), श्री विक्रम कुमार (सीनियर पार्टनर, I»»fcorp Advisory) तथा श्री आलोक श्रीवास्तव (पूर्व विधि सचिव एवं पूर्व सदस्य, NCLAT) शामिल रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ श्री सुधाकर शुक्ला के स्वागत भाषण और पाठ्यक्रम अवलोकन से हुआ। उन्होंने भारत में EÕse of Doi»»fg Busi»»fess के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ—प्रवेश की स्वतंत्रता, संचालन की स्वतंत्रता और निर्गमन की स्वतंत्रता—पर प्रकाश डाला तथा इन्हें कंपनी अधिनियम, 2013; प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002; और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से जोड़ा।

उद्घाटन सत्र की मुख्य विशेषता श्री धनेंद्र कुमार का संबोधन रहा, जो सेवानिवृत्त कक्षर अधिकारी, भारत सरकार के पूर्व सचिव और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने मोनोपोलिज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज (MRTP) अधिनियम से आधुनिक प्रतिस्पर्धा कानून तक की यात्रा का विस्तृत वर्णन करते हुए संस्थान-निर्माण पर अपने अनुभव साझा किए। प्रतिभागियों के साथ उनकी संवादात्मक चर्चा ने सत्र को अत्यंत समृद्ध और प्रेरणादायक बनाया।

सड़क अवसंरचना परियोजनाओं नेटवर्क योजना समूह की 108वीं बैठक संपन्न हुई

(एजेंसी)।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) में नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) की 108वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन करना था। बैठक में विशेष रूप से प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी) के अनुरूप बहुआयामी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार लाने पर जोर दिया गया। एनपीजी ने एकीकृत बहुआयामी अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक केंद्रों तक अंतिम-मील कनेक्टिविटी और 'संपूर्ण सरकारी' दृष्टिकोण के प्रधानमंत्री गतिशक्ति सिद्धांतों के अनुरूप 7 सड़क परियोजनाओं का गहन विश्लेषण किया।

इन पहलों से लॉजिस्टिक्स दक्षता में वृद्धि, यात्रा समय में कमी और परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन और उनके संभावित प्रभाव नीचे विस्तार से दिए गए हैं:

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)

तमिलनाडु में सलेम-कुमारपालयम खंड पर एनएच-544 के छह लेन का निर्माण- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने तमिलनाडु के सलेम-कुमारपालयम खंड पर एनएच-544 के छह लेन वाली सड़क निर्माण परियोजना का प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना के तहत सलेम से कुमारपालयम तक 102.035 किलोमीटर लंबा छह लेन वाला कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो कोच्चि-कोयंबटूर-बेंगलुरु के अत्यधिक व्यस्त मार्ग पर स्थित है। परियोजना के अंतर्गत, शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के आवागमन प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए निरंतर सेवा सड़कों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात प्रवाह को सुचारु बनाने हेतु जंक्शन, इंटरचेंज और ग्रेड सेपरेटर का उन्नयन किया जाएगा। भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस कॉरिडोर में प्रमुख और छोटे पुलों, फ्लाईओवर, रोड-ओवर ब्रिज (आरओबी) और पुलों का निर्माण तथा चौड़ीकरण शामिल है।

इस प्रस्तावित कॉरिडोर के जरिये औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स हब, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और प्रमुख माल परिवहन ढांचों जैसे रेलवे टर्मिनल, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और लॉजिस्टिक्स पार्क तक पहुंच को बेहतर बनाकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार की संभावना है। कोच्चि-कोयंबटूर-बेंगलुरु आर्थिक कॉरिडोर के साथ इस परियोजना का एकीकरण मजबूत करते हुए, यह बेहतर सड़क, रेल, हवाई अड्डा और बंदरगाह संपर्क के माध्यम से कुशल माल ढुलाई, लंबी दूरी के सफर और बहुआयामी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। साथ ही, यह सलेम, इरोड, तिरुप्पुर, कोयंबटूर और होसुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर प्रथम और अंतिम मील संपर्क, हवाई अड्डा कनेक्टिविटी और संचालन में सुधार करेगा। इस परियोजना से कपड़ा, कृषि-प्रसंस्करण, विनिर्माण और कंटेनरीकृत माल परिवहन जैसे क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलेगा।

अमरावती आउटर रिंग रोड का निर्माण (आंध्र प्रदेश) - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में 189.93 किलोमीटर लंबी अमरावती आउटर रिंग रोड (ओआरआर) विकसित करने की योजना बनाई है। यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम करना और विजयवाड़ा, गुंटूर, तेनाली समेत अमरावती राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय संपर्क को सशक्त बनाना है। इस ओआरआर के जरिए यातायात को शहरी केंद्रों से हटाकर शहर के बाहरी इलाकों की ओर मोड़ा जाएगा। इसके साथ ही, विजयवाड़ा हवाई अड्डे तक सुगम पहुंच के लिए विशेष इंटरचेंज उपलब्ध होंगे, और भविष्य में रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर को एकीकृत करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

एक प्रमुख मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के रूप में प्रस्तावित, ओआरआर को राष्ट्रीय जलमार्ग-4 से जोड़ा जाएगा, जो मछलीपटनम और कृष्णापटनम जैसे मुख्य बंदरगाहों को देश के आंतरिक शहरी और औद्योगिक केंद्रों से जोड़ने का कार्य करेगा। इस परियोजना के जरिए यात्रा समय में 30-40 प्रतिशत की कमी, ईंधन की खपत में कमी और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती होने की संभावना है। इससे न केवल कुशल माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

जम्मू-कश्मीर में रफीबाद-कुपवाड़ा-चौकीबल-तंगधार तक पक्की शोल्डर वाली दो लेन सड़क का निर्माण (चौड़ीकरण/मजबूतीकरण)- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में रफीबाद से कुपवाड़ा व चौकीबल होते हुए तंगधार तक पक्की शोल्डर के साथ 62.10 किलोमीटर लंबी दो लेन सड़क के निर्माण (चौड़ीकरण/मजबूतीकरण) का प्रस्ताव पेश किया है। इस परियोजना का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करना है। यह सड़क कुपवाड़ा, चौकीबल, तंगधार और टीटवाल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ते हुए नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास स्थित गांवों तक पहुंच को सुगम बनाएगी। इसके साथ ही, यह सुरक्षा बलों और आवश्यक आपूर्ति की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित कर रक्षा रसद को और भी सशक्त बनाएगी। इस परियोजना के रणनीतिक महत्व के अलावा, इससे दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है। यह परियोजना न केवल पर्यटन, बागवानी और स्थानीय आजीविका को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि एनएच-01, श्रीनगर हवाई अड्डे और सोपोर और बारामूला के रेल नेटवर्क से कनेक्टिविटी बढ़ाकर समग्र क्षेत्रीय विकास में भी योगदान देगी।

भारत में अंतरिक्ष बीमा पारिस्थितिकी तंत्र

(एजेंसी)।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय बीमाकर्ता वैश्विक बीमाकताओं, पुनबीर्माकताओं, जोखिम मूल्' यांकनकताओं और ब्रोकरों (खरीदार और विक्रेता के बीच मध्यस्थ) के सहयोग से विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष बीमा उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। निजी संस्थाएं अपनी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए उपयुक्त बीमा कराने को स्वतंत्र हैं।

अंतरिक्ष संधारणीयता के लिए अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता के बढ़ते महत्व को समझते हुए, अंतरिक्ष उड़ान सुरक्षा और अंतरिक्ष में मलबे कम करने संबंधी केंद्रित प्रयास करने और भीड़भाड़ वाले अंतरिक्ष वातावरण में संचालन की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो की सुरक्षित और संवहनीय अंतरिक्ष संचालन प्रबंधन प्रणाली आईएस4ओएम स्थापित की गई है।

इसरो मिशन-बा' अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्' त राष्' ट्र समिति और अंतर-एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति-आईएडीसी द्वारा अनुशंसित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत अंतरिक्ष मलबे कम करने के दिशानिदेर्शों का यथासंभव पालन करता है।

अंतरिक्ष की सुरक्षा और स्थिरता से संबंधित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, आईएडीसी, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान अकादमी-आईएए, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन-आईएसओ, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ-आईएएफ और संयुक्त राष्ट्र दीर्घकालिक स्थिरता कार्य समूह के सक्रिय सदस्य के रूप में इसरो अंतरिक्ष के सतत उपयोग के लिए प्रासंगिक दिशा-निदेर्शों और संस्' तुतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

भारतीय अंतरिक्ष नीति अंतरिक्ष मलबे कम करने की आवश्यकताओं और अंतरिक्ष मलबे से संबंधित क्षमता निर्माण को महत्वपूर्ण मानती है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मलबा रहित अंतरिक्ष मिशन पहल का नेतृत्व कर रहा है, जिसका उद्देश्य 2030 तक सरकारी या गैर-सरकारी सभी भारतीय अंतरिक्ष संगठनों द्वारा मलबा रहित अंतरिक्ष मिशन पूरा करना है। यह पहल अंतरिक्ष संवहनीयता के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है, जो भारत को बा' अंतरिक्ष गतिविधियों में सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देने वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है।

देश में अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल निजी संस्थाओं को सरकार इन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित और पर्याप्त बीमा लेने को प्रोत्साहित करती है। भारतीय अंतरिक्ष उपकरणों के कारण उत्पन्न होने वाले तृतीय पक्ष नुकसान के लिए सरकार की देयता से संबंधित नीतिगत ढांचा और दिशानिर्देश का मसौदा अभी परामर्श अधीन है। इसमें अन्य बातों के अलावा, प्रक्षेपण संचालकों द्वारा तृतीय पक्ष देयता बीमा का विचार किया गया है, जो जोखिम सुरक्षा प्रदान करने और अंतरराष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों के तहत सरकारों की देयता सुनिश्चित करने के उपायों में एक है।

विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष बीमा पहले से ही उपलब्ध हैं और भारतीय बीमाकर्ता इसे वैश्विक बीमाकताओं, पुनबीर्माकताओं, जोखिम मूल्' यांकनकर्ता और ब्रोकरों के सहयोग से निजी या सरकारी संगठनों को पेश करते हैं। अंतरिक्ष गतिविधियों में अत्यधिक पूंजी निवेश और जोखिम को देखते हुए यह वैश्विक प्रथा है कि विश्व भर के बीमाकर्ता और पुनबीर्माकर्ता जोखिमों के अंश आपस में बांट लेते हैं।

भारतीय मौसम विभाग द्वारा किसानों को प्रदान की जा रही मौसम पूवार्नुमान डेटा

(एजेंसी)।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) सभी राज्यों के किसानों को मौसम पूवार्नुमान प्रदान कर रहा है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (जीकेएमएस) योजना के तहत, आईएमडी जिला और ब्लॉक स्तर पर अगले पांच दिनों के लिए वर्षा, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, बादल आवरण, पवन गति और पवन दिशा का मध्यम-दूरी का मौसम पूवार्नुमान प्रदान करता है, साथ ही मौसम उप-विभाग स्तर पर उसके बाद के सप्ताह की वर्षा और तापमान की दृष्टि प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, अवलोकित मौसम जानकारी और पूवार्नुमानों के आधार पर, देश के 127 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में कार्यरत 130 कृषि-मौसम फील्ड इकाइयाँ (एएमएफयू) अपने-अपने जिलों के लिए अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में हर मंगलवार और शुक्रवार को कृषि-मौसम सलाह तैयार करती हैं, और किसानों के साथ संवाद करके उन्हें दिन-प्रतिदिन की कृषि गतिविधियों के लिए उचित निर्णय लेने में मदद करती हैं।

प्रभाव-आधारित पूवार्नुमान (आईबीएफ) और कृषि के लिए उपयुक्त सलाह भी एएमएफयू द्वारा राष्ट्रीय मौसम पूवार्नुमान केंद्र (एनडब्ल्यूएफसी), नई दिल्ली, और आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम केंद्रों तथा राज्य स्तरीय मौसम केंद्रों (एमसी) द्वारा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के लिए जारी गंभीर मौसम चेतावनियों के आधार पर तैयार की जा रही हैं।

किसानों के कल्याण में सोशल मीडिया का उपयोग

किसानों के मोबाइल फोनों पर मौसम अपडेट और प्रारंभिक चेतावनियाँ सीधे प्रदान करने के लिए, मौसम पूवार्नुमान और कृषि-मौसम सलाह को रीयल-टाइम तंत्रों या बहु-चैनल प्रसारण प्रणालियों के माध्यम से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन, इंटरनेट तथा एसएमएस के जरिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पहलों के तहत प्रसारित किया जाता है। पीपीपी मोड के तहत, लगभग 61.6 लाख किसान मौसम पूवार्नुमान, अलर्ट और कृषि-मौसम सलाह से लाभान्वित हो रहे हैं। चक्रवात, गहन दबाव क्षेत्र आदि जैसे चरम मौसम घटनाओं के दौरान किसान पोर्टल के माध्यम से एसएमएस-आधारित अलर्ट और चेतावनियाँ, साथ ही उपयुक्त उपचारात्मक उपाय भेजे जा रहे हैं।

तकनीकी प्रगति ने पहुंच को और बढ़ाया है, जिससे किसान 'मेघदूत' और 'मौसम' जैसे मोबाइल ऐप्स तथा व्हाट्सएप, फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्थान-विशिष्ट पूवार्नुमान और सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आईएमडी ने 21 राज्य सरकारों के आईटी प्लेटफॉर्म्स के साथ अपनी सेवाओं को एकीकृत किया है, और लगभग 1.56 करोड़ किसान इन राज्य सरकार आईटी प्लेटफॉर्म्स पर अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में मौसम अपडेट की स्थानीय प्रासंगिकता और अंतिम छोर की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए, आईएमडी ने पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के साथ सहयोग में हाल ही में भारत के लगभग सभी ग्राम पंचायतों को कवर करने वाले पंचायत-स्तरीय मौसम पूवार्नुमान शुरू किया है।

ये पूवार्नुमान ई-ग्रामस्वराज

भारत विनिर्माण और लघु एवं मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में शामिल हुआ

(एजेंसी)।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र (बीसीआईसी) में शामिल हुआ। ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) के साथ साझेदारी में ब्रिक्स देशों में विनिर्माण कंपनियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योग 4.0 की दक्षताओं को मजबूत करना है।

इस अवसर पर डीपीआईआईटी के आर्थिक सलाहकार श्री अग्रिम कौशल और यूएनआईडीओ के निदेशक डॉ. क्रिस्टियानो पासिनी ने एक ट्रस्ट फंड समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत बीसीआईसी ढांचे में भारत की भागीदारी को औपचारिक रूप दिया गया।

भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) को ब्रिक्स औद्योगिक दक्षताओं के केंद्र के रूप में नामित किया गया है। एनपीसी डीपीआईआईटी के नीतिगत मार्गदर्शन और यूएनआईडीओ के तकनीकी सहयोग से, ब्रिक्स औद्योगिक दक्षताओं के साथ भारत की सहभागिता का नेतृत्व करेगा और क्षमता निर्माण, उत्पादकता वृद्धि और उन्नत विनिर्माण पद्धतियों को अपनाने में योगदान देगा।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि वन एवं बांस आधारित आर्थिक क्लस्टर को मजबूत करना

(एजेंसी)।

कृषि वन एवं बांस क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम मुख्य रूप से राज्य सरकारें करती हैं। हालांकि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार भी इन क्षेत्रों में विशेष परियोजनाओं को सहायता देकर राज्यों की कोशिशों में मदद करती है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, कृषि वन को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार 2023-24 से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पी एम आर के वी वाई) के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रही है। इस योजना का लक्ष्य नर्सरी स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने और किसानों को खेतों में पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए बीज, पौधे, क्लोन, हाइब्रिड और बेहतर किस्मों सहित अच्छी गुणवत्ता वाली पौधरोपण आपूर्ति करना है। इसे पूरे देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जा रहा है, जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र भी शामिल है। कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों सहित असम में नर्सरी तैयार करने, प्रशिक्षण और मुफ्त पौधा वितरण के लिए सहायता दी गई है।

यह योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कार्य योजना के माध्यम से काम करती है और नर्सरी तथा कृषि वन डेमोंस्ट्रेशन प्लॉट जैसी गतिविधियों की सहायता करती है। असम को 2023-24 से 2024-25 के दौरान 4.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें से 4.09 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिससे 35 नई नर्सरी बनाई गई। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 5.20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, और 51 नई नर्सरी तैयार की गई हैं।

पी एम आर के वी वाई - कृषि वन की शुरूआत 2023-24 में हुई थी जो अब अपने तीसरे साल में है। शुरूआती परिणाम बताते हैं कि पेड़-आधारित कृषि प्रणालियों, जिसमें बांस कृषि - वनीकरण भी शामिल है, के जरिए कृषि आय में विविधता लाने और आजीविका को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। वृक्षारोपण के साथ-साथ इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे किसानों को पेड़ों की फसल के शुरूआती समय में ही कमाई हो सके, उन्हें आर्थिक लाभ मिले और जोखिम कम हो।

इसके अलावा, असम राज्य बांस मिशन (ए एस बी एम) के अंतर्गत बड़े पैमाने पर बांस लगाने की पहल भी की गई है। इससे कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों सहित राज्य में 2019 से 2026 तक लगभग 1,585 हेक्टेयर में बांस लगाए गए। इसके अंतर्गत नर्सरी स्थापित की हैं, जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं, और लगभग 300 किसानों को वैज्ञानिक तरीके से बांस की खेती के लिए प्रशिक्षित किया है। एक अध्ययन में दोनों जिलों में बांस के काफी संसाधन पाए गए, जिससे क्लस्टर विकास योजना बनाने में मदद मिली। मिशन के अंतर्गत उद्यम विकास के लिए असम बांस सम्मेलन जैसे कार्यक्रम संचालित किए गए और महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता के साथ एक बांस अगरबत्ती बनाने वाले क्लस्टर का समर्थन किया। आर्थिक प्रभावों में 6 लाख पौधे लगाना और बांस की अधिक उपज देने वाली किस्मों का वितरण शामिल है, जिससे आजीविका के अवसर पैदा हुए हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण से 400 से अधिक प्रतिभागियों को लाभ हुआ है। इसके अलावा, 1,022 टूलकिट वितरित किए गए, और प्रसंस्कृत बांस उत्पादों को असम पी डब्ल्यू डी रेट शेड्यूल में शामिल किया गया, जिससे बांस कारीगरों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ी है और उनके लिए रोजगार में वृद्धि हुई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस पर आधारित आर्थिक क्लस्टर को बढ़ावा देने के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने हाल ही में दो प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। इनका उद्देश्य बाजार पहुँच, उत्पादों का आधुनिकीकरण और डिजिटल/रिटेल इकोसिस्टम के साथ एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक बांस कारीगर क्लस्टर को मजबूत करना है। साथ ही, क्लस्टर को मजबूत करके और निर्यात में मदद करके इंजीनियर्ड बांस प्रोडक्ट को बढ़ावा देना भी है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

लखनऊः मेट्रो स्टेशन में चेकिंग के दौरान छात्र के बैग से तमंचा मिलने पर हड़कंप, गिरफ्तारी के बाद भेजा गया जेल

(एजेंसी)।

लखनऊ । केडी सिंह बाबू स्टेडियम स्थित मेट्रो स्टेशन पर चेकिंग के दौरान बीकॉम छात्र पीजीआई निवासी अक्षत कनौजिया के बैग में 315 बोर का एक तमंचा मिला। सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ कर हजरतगंज पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर अक्षत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल के मुताबिक मंगलवार को अक्षत बैग लेकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम स्थित मेट्रो स्टेशन पहुंचा। एक्स रे मशीन में चेकिंग के दौरान उसके बैग में तमंचा मिला। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ लिया और सूचना हजरतगंज पुलिस को दी।

हजरतगंज पुलिस अक्षत को पकड़ कर थाने ले गई। पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जनेश्वर मिश्र पार्क के पास उसको तमंचा पड़ा मिला था। उसने तमंचा उठाकर बैग में रख लिया था। एसीपी ने बताया कि अक्षत के खिलाफ दरोगा अंकित कुमार ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है।

समय सीमा गुजरी...50 प्रतिशत ही हो सका लखनऊ-पलिया हाईवे का निर्माण

(एजेंसी)।

शाहजहांपुर। निमार्णाधीन लखनऊ-पलिया हाईवे के निर्माण का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। दिसंबर 2025 तक इसका निर्माण पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक 50 प्रतिशत ही काम पूरा हो पाया है। अब जून 2026 तक इसका निर्माण पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। पुवायां रोड स्थित पैना हायडिल से होते हुए एनएच-30 के पास मौजमपुर तक करीब 13 किमी के बाइपास का निर्माण चल रहा है।

उन्नाव

पैना हाइडिल के पास रिंग रोड के ऊपर से होते हुए करीब 600 मीटर लंबा माइनर ब्रिज बनाया जा रहा है, जो रिंग रोड में आकर मिल जाएगा। इसके अलावा शहबाजनगर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज और गर्रा नदी पर पुल का निर्माण चल रहा है। यह बाइपास बरेली रोड पर मौजमपुर के पास आकर मिलेगा।

यहां पर अंडरपास का निर्माण कराया जाएगा। इसके निर्माण से

पलिया, पूरनपुर, पुवायां व बंडा-खुटार से आने या जाने वालों को शहर से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहर में लगने वाले जाम से छुटकारा मिलेगा। बाइपास से दोनों हाईवे को जोड़ा जा रहा है। चांदापुर चौराहा से आगे गर्रा नदी और और दनियापुर चौड़ेरा गांव के पीछे खन्नौत नदी पर पुल का निर्माण बहुत धीमी गति से चल रहा है।

मौजमपुर के पास नेशनल हाईवे पर वाहनों के आवागमन में दिक्कत

पुवायां रोड से दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजमपुर के पास नेशनल हाईवे पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस निर्माण की वजह से दिल्ली और लखनऊ की ओर से आने-जाने वाले वाहनों को निकलने में परेशानी हो जाती है। आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। इसके निर्माण के बाद भी राहगीरों को राहत मिल पाएगी। यहां पर अंडरपास का निर्माण भी हो रहा है।

सात अंडरपास का हो रहा निर्माण

पलिया हाईवे को दिल्ली-लखनऊ हाईवे से चांदापुर जाने वाली रोड के पास जोड़ा जाएगा। शाहाबाद तक रास्ते में पड़ने वाली सड़कों पर अंडरपास बनाए जाने का काम भी शुरू हो गया है। शाहजहांपुर से खुटार सीमा तक सड़क का चौड़ीकरण लगभग पूरा हो गया है। शाहजहांपुर-पुवायां रोड से लेकर हरदोई सीमा तक करीब सात अंडरपास का निर्माण हो रहा है।

पालिया-लखनऊ हाईवे का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। बाढ़ जाने की वजह से बीच में काम प्रभावित हुआ था। अब इसका निर्माण जून तक पूरा कर लिया जाएगा।

- नवरत्न, पीडी, एनएचएआई

गाजियाबाद के बाद अब लखनऊ में बड़ी घटना, बच्चे ने लगा ली फांसी, मां की डांट से हो गया था गुस्सा

लखनऊः (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के बाद अब राजधानी लखनऊ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मां की डांट से आहत बेटे ने फंदे से लटक कर जान दे दी. दसवीं के छात्र प्रतीक आनंद ने स्कूल में प्रैक्टिकल की फाइल जमा नहीं की थी. इसके बाद स्कूल ने प्रतीक की मां आशा को मैसेज भेजा था. मैसेज मिलने पर मां ने दसवीं में पढ़ रहे बेटे को डांटा था. 16 वर्षीय प्रतीक आनंद पवन पुरी के निजी स्कूल का छात्र था. प्रतीक के पिता कृष्णकांत आनंद की 2009 में बीमारी से मौत हो गई थी. मां और बड़े भाई प्रसार आनंद के साथ आलमबाग में प्रतीक रह रहा था. काम पूरा न होने के चलते प्रतीक ने स्कूल में प्रैक्टिकल की फाइल जमा नहीं की थी. इसके बाद स्कूल से प्रतीक की मां आशा को मैसेज भेज दिया गया.

स्कूल वालों ने मैसेज भेजा कि प्रैक्टिकल की फाइल जमा नहीं होगी तो प्रतीक का साल बर्बाद हो सकता है. स्कूल का मैसेज देखकर मंगलवार शाम मां आशा ने बेटे प्रतीक को फटकार लगाई. इसके बाद प्रतीक अपने कमरे में चला गया. शाम को 6 बजे मां ने प्रदीप को चाय पीने के लिए बुलाया. कोई आवाज न आने पर दरवाजा खटखटाया. दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों को बुलाया।

बता दें कि गाजियाबाद जिले में मंगलवार-बुधवार की रात को तीन बहनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली. खुदकुशी की जांच में जुटी पुलिस को कई अहम सबूत मिले. जांच के दौरान पता चला कि बच्चियों से घरवालों ने उनका फोन छीन लिया था, जिससे वह नाराज हो गई थीं. बच्चियां कोरियन कल्चर से ज्यादा प्रभावित थीं. यहां तक की उन्होंने अपना कोरियन नाम भी रख रखा था. बुधवार की देर रात पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दी लखनऊ के रेहड़ी-पटरी के दुकानदारों को राहत

(एजेंसी)।

लखनऊ, चार फरवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी के रेहड़ी-पटरी वालों को राहत देते हुए लखनऊ नगर निगम को निर्देश दिया कि ऐसे दुकानदारों को तब तक न हटाया जाए, जब तक 'टाउन वेंडिंग कमेटी' शहर भर का सर्वेक्षण करके प्रमाणपत्र जारी नहीं कर देती, बशर्ते ऐसी दुकानें यातायात में बाधा न डालें।

उच्च न्यायालय ने नगर निगाम को 'वेंडिंग प्लान' तैयार करने के लिए भी कहा। मामले की अगली सुनवाई तीन महीने बाद की जाएगी।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ए.के. कुमार चौधरी की खंडपीठ ने अमीनाबाद इलाके के अमर कुमार सोनकर और अन्य रेहड़ी पटरी वालों की याचिका पर यह आदेश दिया।

पीठ ने कहा कि जब तक कानून के अनुसार सर्वे पूरा नहीं हो जाता, राज्य सरकार द्वारा वेंडिंग प्लान को मंजूरी नहीं मिल जाती और सभी पात्र रेहड़ी पटरी दुकानदारों को 'वेंडिंग सर्टिफिकेट' जारी नहीं हो जाते, तब तक ऐसे दुकानदारों को रेहड़ी पटरी दुकानदार (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम 2014 की धारा 3(3) के तहत कानूनी सुरक्षा मिलती रहेगी।

याचिकाकताओं ने बताया कि हालांकि सर्वे पूरा हो गया था लेकिन अभी तक वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे। इसके बावजूद उन्हें उनकी मौजूदा जगहों से हटाया जा रहा था जो उनके अनुसार अधिनियम के उद्देश्यों के विपरीत था।

नीतिगत पहल से राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने विभिन्न हितधारकों को एकजुट किया है

(एजेंसी)।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना 22 जनवरी 2015 को बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) और लड़कियों तथा महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना एक नीतिगत पहल से एक राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गई है, जिसमें सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों को एकजुट किया गया है।

नीति आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं के वित्तीय वर्ष 2019 से 2024 तक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन में पाया कि मिशन शक्ति की उप-योजना संबल जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी शामिल है, जो अत्यंत

प्रासंगिक है और एकीकृत एवं डेटा-आधारित सेवाओं के माध्यम से समाधान करती है। मूल्यांकन में प्राथमिक और द्वितीयक शोध की व्यावहारिक मिश्रित पद्धति अपनाई गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात वर्ष 2014-15 में 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2014-15 में 75.51 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 80.2 प्रतिशत हो गया है।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

कोयंबत्तूर - जयपुर स्पेशल ट्रेन के फेरे पुनः विस्तारित

यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कोयंबत्तूर = जयपुर के फेरों को पुनः विस्तार किया गया है।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ट्रेन संख्या 06181 कोयंबत्तूर- जयपुर स्पेशल दिनांक 19 फरवरी 2026 तक कोयंबत्तूर से प्रति गुरुवार को प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 06182 - जयपुर -कोयंबत्तूर स्पेशल दिनांक 22 फरवरी 2026 तक जयपुर से प्रति रविवार को प्रस्थान करेगी।

यात्रीगण ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

जनसंपर्क विभाग पश्चिम रेलवे, रतलाम मंडल

उत्तर रेलवे में ब्लॉक के कारण इंदौर-शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर एक्सप्रेस प्रभावित

रतलाम, 04 फरवरी। उत्तर रेलवे में निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेने प्रभावित रहेगी । ब्लॉक कार्य के कारण पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इंदौर से संचालित होने वाली इंदौर-शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर-इंदौर एक्सप्रेस भी प्रभावित रहेगी।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 मई 2026 तक इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्या 22941 इंदौर - शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर एक्सप्रेस, जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा जालंधर कैंट से शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर तक निरस्त रहेगी। इसी प्रकार 27 मई 2026 तक शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 22942 शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर - इंदौर एक्सप्रेस, जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा शहीद कैप्टन तुषार महाजन इंदौर उधमपुर से जालंधर कैंट तक निरस्त रहेगी।

ट्रेनों के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

जनसंपर्क विभाग पश्चिम रेलवे, रतलाम मंडल

हापा - नाहरलगून स्पेशल ट्रेन के फेरे पुनः विस्तारित

रतलाम, 04 फरवरी। यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर परिचालित गाड़ी संख्या 09525 हापा - नाहरलगून स्पेशल की सेवाओं का विस्तार किया गया है।

गाड़ी संख्या 09525 हापा - नाहरलगून स्पेशल को पहले 25 फरवरी 2026 तक तथा गाड़ी संख्या 09526 नाहरलगून - हापा स्पेशल को 28 फरवरी 2026 तक अधिसूचित किया गया था, जिसे अब बढ़ाते हुए दोनों दिशाओं में अतिरिक्त फेरे चलाने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गाड़ी संख्या 09525 हापा - नाहरलगून स्पेशल हापा से 04 मार्च 2026 से 30 दिसंबर 2026 तक एवं इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09526 नाहरलगून - हापा स्पेशल नाहरलगून से 07 मार्च 2026 से 02 जनवरी 2027 तक अतिरिक्त फेरे लगाएगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि कोच एवं ट्रेन संचालन संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए www. enquiry. indianrail. gov.inवेबसाइट, रेल मदद ऐप अथवा 139 रेल मदद नंबर का उपयोग करें।

जनसंपर्क विभाग
रतलाम मंडल

अहमदाबाद - दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस समय में आंशिक बदलाव

रतलाम, 04 फरवरी। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से गुजरने वाली अहमदाबाद - दरभंगा साबरमती एक्स सप्रेस का अहमदाबाद एवं दरभंगा से प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। विवरण इस प्रकार है -

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गाड़ी संख्या 19165 अहमदाबाद - दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस -06 फरवरी, 2026 से अहमदाबाद स्टेशन से 19.15 बजे के स्थान पर 19.25 बजे प्रस्थान करेगी। इसीप्रकार गाड़ी संख्या 19166 दरभंगा - अहमदाबाद साबरमती एक्स सप्रेस -01 अप्रैल 2026 से यह ट्रेन दरभंगा स्टेशन से 04.30 बजे के स्थान पर 04.20 बजे प्रस्थान करेगी। अन्य स्टेशनों पर इसके आगमन/प्रस्थान समय में कोई बदलाव किया गया।

यात्रीगण कृपया कोच एवं ट्रेन संचालन संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए www. enquiry. indianrail. gov.in वेबसाइट, रेल मदद ऐप अथवा 139 रेल मदद नंबर का उपयोग करें।

जनसंपर्क विभाग
पश्चिम रेलवे, रतलाम मंडल

लखनऊः बाइक सवार युवक के गले में फंसा चाइनीज पतंग का मांझा, नसें कटने से हुई दर्दनाक मौत

लखनऊ , (एजेंसी)। ाजारखाला में हैदरगंज ओवरब्रिज पर बुधवार को चाइनीज मांझे ने बाइक से जा रहे दुबग्गा के सीते बिहार निवासी सैयद शोएब (34) की जान ले ली। मांझा इतना सख्त था कि उससे शोएब के गले की नस कट गई। वह अनियंत्रित होकर बाइक से सड़क पर गिर पड़े। ट्रॉमा सेंटर में शोएब की जान चली गई।

इंस्पेक्टर बाजारखाला बृजेश सिंह ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे शोएब मिल एरिया चौकी की ओर से हैदरगंज की ओर जा रहे थे। ओवर ब्रिज पर अचानक मांझा उनकी गर्दन में फंस गया। शोएब ने एक हाथ से मांझे को पकड़कर उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वह और उलझता चला गया। इसी दौरान शोएब की बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। शोएब सड़क पर काफी दूर तक घिसटते चले गए। शोएब की गर्दन पूरी तरह मांझे में उलझ गई। मांझे से उनके गले की नस कट गई। शोएब के गले से खून की धार निकलने लगी। वह दर्द से सड़क पर लहूलुहान तड़पने लगे। खून से शोएब का पूरा शरीर लाल हो गया। राहगीरों ने ईरिक्शा पर शोएब को लादा और उन्हें ट्रॉमा सेंटर लेकर गए।

राहगीरों ने दिखाई मानवता, खाली कराया रास्ता

शोएब को खून से लथपथ देखकर राहगीरों ने मानवता दिखाई। बाइक सवार राहगीर ईरिक्शा के आगे आगे ट्रैफिक खाली कराते हुए शोएब को ट्रॉमा सेंटर तक लेकर गए। हालांकि, इलाज के दौरान शोएब की जान चली गई। ट्रॉमा सेंटर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. प्रेमराज ने बताया कि घायल का अत्यधिक खून बह चुका था। इसकी वजह से तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। उधर, पुलिस ने भी हैदरगंज चौराहे पर रास्ता खाली कराकर ईरिक्शा को रास्ता दिलाया। इंस्पेक्टर का कहना है कि घटनास्थल पर चालक का हेलमेट मिला है। बाइक कब्जे में ले ली गई है।

पत्नी ने अज्ञात के खिलाफ दी तहरीर

शोएब की पत्नी ने बाजाखाला थाने में तहरीर दी है। आरोप है कि ओवर ब्रिज के पास अज्ञात व्यक्ति पतंग उड़ा रहा था। पतंग का मांझा शोएब के गर्दन में फंस गया, जिसके कारण उनकी जान चली गई। पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर छानबीन की जाएगी। किस मांझे से शोएब के गले की नस कटी है, इसके बारे में भी पता लगाया जाएगा।

काम से निकले थे शोएब

साढू सैयद नदीम रजा ने बताया कि बुधवार दोपहर शोएब बाइक से ऑफिस के काम से निकले थे। शोएब पहले भोलानाथ कुआं पर रहते थे। बाद में वह दुबग्गा शिफ्ट हो गए थे। शोएब मां आब्दा बानो, पत्नी फौजिया, दो बेटियां बुशरा और इकरा के साथ रहते थे। वह एक फार्मा कंपनी में एमआर थे। परिजनों ने बताया कि शोएब के गले में लगभग छह सेंटीमीटर का गहरा घाव हो गया था। राहगीरों ने शोएब के फोन से परिजनों को घटना की जानकारी दी थी। शोएब के पिता सैयद आरिफ का 20 वर्ष पूर्व देहांत हो गया था। शोएब की एक बहन डॉ. शैला परवीन हैं।

शोएब के पिता सैयद आरिफ ने दो शादियां की थी। शोएब दूसरी पत्नी आब्दा के बेटे थे।

लखनऊ डीएम की मदद से दिव्यांग महिला को मिली ई-स्कूटी:बच्चे का स्कूल में एडमिशन हुआ, बोली- अब आत्मनिर्भर बनूंगी

लखनऊ, (एजेंसी)। लखनऊ में दिव्यांग महिला को प्रशासन के सहयोग से इलेक्ट्रिक 3-व्हील स्कूटी दी गई है। महिला ने 29 जनवरी 2026 को जनता दर्शन के दौरान जिलाधिकारी विशाख जी. को प्रार्थना पत्र देकर मदद मांगी थी।

जिलाधिकारी के निर्देश पर आज, 4 फरवरी को जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय की ओर से उन्हें स्कूटी सौंपी गई। उनके 6 साल के बेटे का स्कूल में एडमिशन भी कराया गया।

पारा निवासी दिव्यांग खुशबू चलने-फिरने में असमर्थ हैं। घर से बाहर निकलना, रोजमर्रा के काम करना और अपने 6 साल के बेटे को साथ लेकर आना-जाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। उन्होंने अपनी समस्या प्रशासन तक पहुंचाने का फैसला किया।

जनता दर्शन के दौरान मांगी मदद

29 जनवरी 2026 को जनता दर्शन के दौरान खुशबू ने जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि बिना किसी सहारे के आने-जाने में काफी दिक्कत होती है। उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर या ई-स्कूटी की जरूरत है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। अपने बच्चे की देखभाल कर सकें।

इस पर जिलाधिकारी ने मामले में जिला दिव्यांगजन अधिकारी शशांक सिंह को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। इस पर शशांक सिंह ने खुशबू की समस्या के समाधान की प्रक्रिया शुरू कराई। प्रशासनिक सहयोग से उनके बेटे का स्कूल में दाखिला कराया।

दिव्यांगग खुशबू को ई-स्कूटी मिली है। इससे वह काफी खुश हैं।

सरकारी योजना नहीं थी, उरफ से ई-स्कूटी दिलाई

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से फिलहाल ई-स्कूटी या ई-वाहन की कोई शासकीय योजना संचालित नहीं है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि खुशबू को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उरफ के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाए।

इसके बाद उरफ सहयोग के जरिए 4 फरवरी 2026 को जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय, लखनऊ में खुशबू को इलेक्ट्रिक 3-व्हील स्कूटी सौंपी गई।

जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा

ई-स्कूटी मिलने के बाद खुशबू ने बताया कि अब उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। वह अपने बच्चे के साथ बाहर जा पाएंगी। रोजमर्रा के काम आसानी से पूरे कर पाएंगी। भविष्य में स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास बढ़ेगा।

खुशबू ने उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का आभार जताया है। उनका कहना है कि इस सहयोग से वह अब सम्मानपूर्वक और आत्मनिर्भर जीवन की ओर कदम बढ़ा सकेंगी।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने ओडिशा के रायरंगपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (4 फरवरी, 2026) ओडिशा के रायरंगपुर में महाराजा श्रीराम चंद्र भंजा देव विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी परिसर का उद्घाटन किया और आयुष अस्पताल सह आयुर्वेदिक कॉलेज, ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर, तीरंदाजी केंद्र, शहर सौंदर्यीकरण और जल निकासी उन्नयन परियोजनाओं, सभागार और सांस्कृतिक केंद्र, लड़कियों के छात्रावास और नशामुक्ति केंद्र की आधारशिला रखी।

इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार की पूर्वोदय परिकल्पना ओडिशा के विकास को प्राथमिकता देती है और मयूरभंज जिला इस परिकल्पना से काफी लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये विकासोन्मुखी परियोजनाएं, संस्थाएं और योजनाएं इस क्षेत्र को लाभ पहुंचाएंगी और यहां के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार जनजातीय भाइयों और बहनों के आर्थिक विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री वन धन योजना के माध्यम से 90 से अधिक लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उपलब्ध कराना, सूक्ष्म ऋण योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के आदिवासी सदस्यों को ऋण देना और आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के तहत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता के कुछ उदाहरण हैं। सरकार बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के लिए भी काम कर रही है। निजी समूहों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री-जनमन योजना लागू की गई है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विद्युतीकरण किया गया है और दूरदराज के क्षेत्रों में 4जी इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। इन प्रयासों से आदिवासी क्षेत्रों में समग्र विकास की धारा प्रवाहित हो रही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदाय के विकास के माध्यम से ही सबसे गरीब लोगों के उत्थान का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है कि जनजातीय समुदायों को सभी सरकारी कल्याणकारी और विकास योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने सभी से इन योजनाओं का लाभ उठाने और दूसरों को भी जागरूक करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय विकास सुनिश्चित होगा, जिससे राज्य का विकास होगा और अंततः देश का विकास होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने का हमारा संकल्प सरकार और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से ही पूरा हो सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा

राष्ट्रीय एसईसी सम्मेलन 25 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है

(जीएनएस)।

1- भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) 24 फरवरी, 2026 को राज्य निर्वाचन आयुक्तों (एसईसी) के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों के इस सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। यह सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा।

2- राष्ट्रीय एसईसी सम्मेलन 25 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। पिछला ऐसा सम्मेलन वर्ष 1999 में हुआ था।

3- मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और उद्घाटन समारोह में राज्य निर्वाचन आयुक्तों को संबोधित करेंगे।

4- राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ सम्मेलन में भाग लेंगे और अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। ईसीआई के सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) भी राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे।

5- सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के संबंध में अपने-अपने कानूनी ढाँचों के भीतर चुनाव आयोग (ईसीआई) और चुनाव सुरक्षा आयोग (एसईसी) के कामकाज में तालमेल स्थापित करना है।

6- प्रतिभागी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता पात्रता से संबंधित चुनावी कानूनों, चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए तकनीकी हस्तक्षेपों जैसे कि हाल ही में लॉन्च किए गए ईसीआईनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म और ईवीएम आदि पर चर्चा सत्रों में भाग लेंगे।

7- भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) भारत के संविधान और देश के कानूनी ढांचे के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने के अपने अनुभव से भी विशेषज्ञता प्रदान करेगा।

8- राज्य चुनाव आयोगों का गठन संबंधित राज्यों के कानून द्वारा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के अधिकार प्रदान करने वाले प्रावधानों के तहत किया गया है। एसईसी को पंचायतों और नगर निकायों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण सौंपा गया है।

ड्रोन के विद्युतचुंबकीय व्यतिकरण (ईएमआई) और विद्युतचुंबकीय संगतता (ईएमसी) परीक्षण को साकार करने के लिए एनटीएच ने एसटीक्यूसी-ईआरटीएल (नॉर्थ) के साथ साझेदारी की

इस नई साझेदारी से भारत का ड्रोन प्रमाणन तंत्र को मजबूती मिलेगी

इस नए सहयोग से सुरक्षा, सामर्थ्य और वैश्विक स्वीकृति को बढ़ावा मिलेगा

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र (एनटीएच) ने केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया', ' आत्मनिर्भर भारत' और ' विजन 2047' के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए भारत को सुरक्षित, विश्वसनीय और प्रमाणित ड्रोन प्रौद्योगिकियों के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र (एनटीएच) ने इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एसटीक्यूसी) निदेशालय- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर) [ईआरटीएल (उत्तर)] के साथ सहयोग समझौता किया है। इससे ड्रोनों का विद्युतचुंबकीय व्यतिकरण (ईएमआई) और विद्युतचुंबकीय संगतता (ईएमसी) परीक्षण संभव हो सकेगा जिससे भारत के ड्रोन परीक्षण एवं प्रमाणन ढांचे को मजबूती मिलेगी।

यह सहयोग ड्रोन नियम, 2021 और मानवरहित विमान प्रणालियों के लिए प्रमाणन योजना (सीएसयूएएस), 2022 के तहत एक महत्वपूर्ण नियामक आवश्यकता को पूरा करता है। साथ ही, यह भारत की सुरक्षित, विश्वसनीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करने वाली मानवरहित विमान प्रणालियों (यूएएस) को प्रमाणित करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा।

उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव श्रीमती निधि खरे, राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र के महानिदेशक डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव, एसटीक्यूसी निदेशालय के वैज्ञानिक 'जी' श्री विवेक कश्यप और ईआरटीएल (उत्तर) के वैज्ञानिक 'एफ' और निदेशक श्री प्रदीप गुंज्याल की उपस्थिति में 2 फरवरी 2026 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

इस प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, ड्रोन और उनके उप-प्रणालियों का ईएमआई/ईएमसी और प्रतिरक्षा परीक्षण ईआरटीएल (उत्तर) में लागू आईईसी 61000 / आईएस 14700 मानकों के अनुसार किया जाएगा जबकि एनटीएच शेष परीक्षण अपने परिसर में करेगा। इस सहयोग के माध्यम से प्राप्त परीक्षण रिपोर्टों को टाइप सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में सहजता से एकीकृत किया जाएगा जिससे ड्रोन निमार्ताओं, विशेष रूप से स्टार्टअप और एमएसएमई को एक पारदर्शी, सुगम, विश्वसनीय और सरकार समर्थित प्रमाणन प्रक्रिया प्राप्त होगी।

यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण उच्च लागत वाली अवसंरचना के दोहराव से बचाता है, मौजूदा राष्ट्रीय सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है और भारत में ड्रोन सुरक्षा व विश्वसनीयता के लिए नियामक ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ करता है। इसके साथ ही, यह दृष्टिकोण यह भी सुनिश्चित करता है कि एनटीएच एनटीएच द्वारा प्रमाणित ड्रोनों का आईईसी/आईएसओ, एमआईएल-एसटीडी, एएसटीएम और आरटीसीए जैसे वैश्विक मानकों पर खरा उतरना संभव हो, जिससे भारतीय ड्रोनों की अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति में उल्लेखनीय वृद्धि हो।

विश्व स्तरीय ड्रोन परीक्षण और प्रमाणीकरण को निजी सुविधाओं की तुलना में काफी कम लागत पर सुलभ और किफायती बनाकर, यह पहल कृषि, लजिस्टिक, स्वास्थ्य सेवा, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचा निगरानी और स्मार्ट शहरों जैसे क्षेत्रों में नवाचार को गति देगी।

एनटीएच और एसटीक्यूसी-ईआरटीएल (नॉर्थ) के बीच प्रस्तावित यह सहयोग, एनटीएच की ड्रोन प्रमाणन क्षमताओं का विस्तार करने और देश के लिए एक मजबूत, स्वदेशी और भविष्य के लिए तैयार ड्रोन प्रमाणन व्यवस्था के निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र (एनटीएच) को डीजीसीए और क्यूसीआई द्वारा मानवरहित विमान प्रणाली प्रमाणन योजना (सीएसयूएएस) के तहत एक प्रमाणन निकाय (सीबी)/अधिकृत परीक्षण इकाई (एटीई) के रूप में अनुमोदित किया गया है और यह ड्रोन सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए सुरक्षा, गुणवत्ता और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एनटीएच भारत सरकार का एक प्रमुख वैज्ञानिक एवं परीक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी और यह उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के साथ, राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण, निरीक्षण, गुणवत्ता आश्वासन और प्रमाणन सेवाएं प्रदान करता है।

देश को बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित 'बाल विवाह मुक्त भारत' जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 6 करोड़ से अधिक नागरिकों तक यह संदेश पहुंचाया गया

(जीएनएस)।

केंद्र सरकार ने 27 नवंबर 2024 को 'बाल विवाह मुक्त भारत' नामक राष्ट्रीय अभियान की शुरूआत की थी जिसका मुख्य उद्देश्य देश को बाल विवाह से पूरी तरह मुक्त बनाना है। इस पहल के तहत 'समग्र सरकारी' और 'समग्र सामाजिक' दृष्टिकोण अपनाते हुए 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण माना गया है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य बाल विवाह रोकने के लिए व्यापक जागरूकता फैलाना, माता-पिता, परिवार और समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) की क्षमता और भूमिका को प्रभावी बनाना, बाल विवाह से जुड़े मामलों की समय पर रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना, साथ ही उन किशोरियों की पहचान करना है जो स्कूल छोड़ चुकी हैं या जिन पर बाल विवाह का खतरा मंडरा रहा है। इसके माध्यम से उनकी शिक्षा, कौशल विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 4 दिसंबर 2025 को 100 दिनों का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य इस पहल की सफलता का उत्सव मनाने और इसे और अधिक प्रभावी बनाना है। इस अभियान का मुख्य मकसद सभी संबंधित पक्षों को एक योजनाबद्ध और निर्धारित समय सीमा के तहत जोड़ना है। इसके साथ ही, यह अभियान संस्थानों, सामुदायिक नेताओं और सेवा प्रदाताओं तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही, इसमें बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) की जानकारी को अनिवार्य रूप से बीवीएमबी पोर्टल पर अपलोड करने पर भी जोर दिया गया है।

यह अभियान एक व्यवस्थित और चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना के तहत संचालित है। पहले चरण में (27 नवंबर , 2025 से 31 दिसंबर, 2025) विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वाद-विवाद, निबंध प्रतियोगिताओं और शपथ समारोहों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। दूसरे चरण (1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026) का मुख्य उद्देश्य धार्मिक संस्थानों और विवाह संबंधित सेवा प्रदाताओं, जैसे मंदिर, मस्जिद, खानपान सेवाएं, टेंट हाउस और डीजे इत्यादि के साथ सहयोग स्थापित करना है, ताकि बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता फैलाई जा सके और सूचनात्मक एवं शैक्षिक सामग्री प्रदर्शित की जा सके।

केंद्रीय मंत्री को गद्दार कहे जाने पर भड़का सिख समुदाय:राहुल गांधी के बयान के विरोध में लखनऊ में फूंका गया पुतला

लखनऊ, (जीएनएस)। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर राहुल गांधी के बयान ने सिख समुदाय में नाराजगी बढ़ा दी है। राहुल गांधी द्वारा रवनीत सिंह बिट्टू को ह्लगद्दारह्व कहे जाने के बाद लखनऊ में सिख संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका।

शहर के आलमबाग इलाके में सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। गुरुगोविंद सिंह समिति के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के बयान को सिख समाज के लिए अपमानजनक बताया और तत्काल माफी की मांग की।

आलमबाग में सिख संगठनों का

जोरदार विरोध — आलमबाग स्थित खालसा चौक

पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी के बीच राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब मामला सिख समाज से जुड़ा हो।

बयान से आहत सिख समाज

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि रवनीत सिंह बिट्टू को ह्लगद्दारह्व कहे जाने से पूरे सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। सिख संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि इस तरह के बयान दोहराए गए तो विरोध और तेज किया जाएगा।

बीमार बच्चों के सैंपल जांच के लिए भेजे लखनऊ

कर्णप्रयाग। मठकोट में बीमार बच्चों की बीमारी का कारण जानने के लिए लिए गए खून के नमूनों की जांच लखनऊ प्रयोगशाला से होगी। बीते सोमवार को यहां एहतियातन के तौर पर 23 बच्चों के खून के नमूने लिए गए थे। जनवरी अंतिम सप्ताह में गांव में करीब 40 बच्चे बुखार से पीड़ित थे। स्वास्थ्य विभाग ने यहां शिविर लगाकर उनकी जांच की। अब बीते सोमवार को बच्चों के खून के सैंपल विभाग ने जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेजे हैं। सीएमओ डॉ. अभिषेक गुप्ता ने बताया कि सैंपल को यहां से देहरादून और देहरादून से लखनऊ प्रयोगशाला भेजा गया है।

गैरसैंण अस्पताल में विशेषज्ञ मिले तो होने लगा उपचार

कर्णप्रयाग। गैरसैंण अस्पताल की सेहत में सुधार होने लगा है। विभाग ने यहां चार विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात कर दिए हैं। इनमें महिला रोग विशेषज्ञ ने बीते सप्ताह की कार्यभार लिया है। ऐसे में अब लोगों को अस्पताल में उपचार मिलने की उम्मीद बंध गई है।

ग्रीष्मकालीन राजधानी के अस्पताल गैरसैंण में सुविधाओं के लिए लोग आंदोलित थे। बीते वर्ष लोगों ने कई बार यहां प्रदर्शन किया। इसके बाद यहां बाल रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ की तैनाती हुई। बीते माह ही अस्पताल में महिला रोग और निश्चेतक की तैनाती कर दी गई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में ग्रामीणों को उपचार के लिए 50 किमी दूर कर्णप्रयाग और 70 किमी से अधिक दूर रानीखेत जाना पड़ता था। सीएमओ डॉ. अभिषेक गुप्ता ने बताया कि गैरसैंण में हाल ही में शासन ने महिला रोग विशेषज्ञ की तैनाती की थी। इस पर बीते सप्ताह महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. शिल्पा ने अस्पताल में तैनाती दे दी है। इससे पहले यहां निश्चेतक ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया था। जबकि बाल रोग और हड्डी रोग विशेषज्ञ पहले ही तैनात थे। अस्पताल में चार-पांच मेडिकल ऑफिसर भी तैनात हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और आईपीई ग्लोबल लिमिटेड ने महिला-केंद्रित कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु गठजोड़ किया

(जीएनएस)।

कौशल सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने आज आईपीई ग्लोबल लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिससे पूरे भारत में युवा महिला केंद्रित, लिंग-संवेदनशील और भविष्य के लिए तैयार कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया जा सके। यह गठजोड़ कार्यक्रम डिजाइन को बेहतर बनाने, महत्वाकांक्षी रोजगार भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, और कौशल विकास, रोजगार योग्यता और समावेशी आर्थिक विकास के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

इस अवसर पर, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की सचिव श्रीमती देबश्री मुखर्जी ने कहा, ह्लमहिलाओं का कौशल विकास भारत की समावेशी वृद्धि और कार्यबल परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। आईपीई ग्लोबल के साथ यह साझेदारी हमारे उस संकल्प को दर्शाती है, जिसमें हम एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जहाँ विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों की युवा महिलाएं महत्वाकांक्षी अवसरों, सम्मानजनक रोजगार मार्गों, और बदलती अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए आवश्यक समर्थन प्रणालियों तक पहुँच सकें।ह्व

अ ॅ१ङ्क४स्र ङ्का स्रीङ्क्स्र ी २३ल्ल्र्ल्लि ॅल्ल ा१ङ्कल्ल३ ङ्का ३ ीअक ल्ली१३ी ङ्कल्ल३ील्ल३ ८ ु ॅल्लूङ्क१११३.

यह साझेदारी भारत के कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाएगी, जो महिलाओं की भागीदारी और कौशल विकास में परिणामों को सुधारने के उद्देश्य से साक्ष्य-आधारित, लिंग-संवेदनशील उपायों के माध्यम से संचालित होगी। यह गठजोड़ संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने, प्रशिक्षण को उद्योग की मांग के अनुरूप बनाने, और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से रोजगार मार्गों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित होगा।

इस साझेदारी में महिलाओं की कौशल विकास और औपचारिक रोजगार में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी राष्ट्रीय जागरूकता अभियान, लिंग-संवेदनशील भर्ती प्रतिबद्धताओं के माध्यम से नियोक्ताओं की अधिक भागीदारी, और डेटा-आधारित शासन का समर्थन करने के लिए सुदृढ़ निगरानी तंत्र शामिल हैं। यह पहल किशोरियों के लिए एमएसडीई के विशेष कौशल विकास प्रयासों को भी सुदृढ़ करेगी, जिससे अधिक समावेशी, परिणाम-केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार कौशल विकास मॉडल तैयार होंगे।

मनेकशॉ सेंटर में फ्यूचर वारफेयर कोर्स 3.0 में संज्ञानात्मक और साइबर डोमेन पर जोर

(जीएनएस)।

नई दिल्ली के मनेकशॉ सेंटर में 02 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित त्रि-सेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स (एफडब्ल्यूसी-3) का तीसरा संस्करण संज्ञानात्मक और साइबर युद्ध मॉड्यूल में प्रवेश किया है, जो संघर्ष के उभरते डोमेन को समझने और युद्ध के विकसित स्वरूप के लिए एक महत्वपूर्ण खंड है।

यह मॉड्यूल कोर्स के समग्र उद्देश्य के अनुरूप है, जिसमें अधिकारियों को साइबर, सूचना और संज्ञानात्मक युद्ध की व्यापक समझ प्रदान करना, परिचालन दूरदृष्टि और अनुकूलनशील सोच को बढ़ावा देना शामिल है।

चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी के चेयरमैन को इंटीग्रेटेड स्टाफ के चीफ (सीआईएससी) एयर मार्शल अशुतोष दीक्षित ने अपने संबोधन में उजागर किया कि भविष्य के संघर्ष पारंपरिक अभियानों के साथ-साथ साइबर और संज्ञानात्मक आयामों में आकार लेते जाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि सैन्य निर्णय-प्रक्रिया, परिचालन योजना और रणनीतिक लाभ जटिल सूचना वातावरण में नेविगेट करने, विरोधी प्रभाव अभियानों का मुकाबला करने तथा डिजिटल और संज्ञानात्मक उपकरणों का प्रभावी उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि भारत की तैयारियों को विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता और परिचालन श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए इसका जबरदस्त महत्व है।

इस कोर्स में भाग लेने वालों की बहु-विषयी संरचना है, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी, डीआरडीओ वैज्ञानिक, अकादमिक जगत तथा प्रौद्योगिकी और रक्षा उद्योग साझेदारों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इन्होंने यहां अपने विचारों के गतिशील आदान-प्रदान को बेहद सुगम बनाया।

इस वातावरण ने प्रतिभागियों को बहु-डोमेन अभियानों में संज्ञानात्मक और साइबर क्षमताओं के एकीकरण की खोज करने तथा एआई, न्यूरल नेटवर्क और स्वचालित खुफिया प्रणालियों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का परिचालन लाभ के लिए उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसका

सरकार ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समर्थन तथा सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं

(जीएनएस)।

सरकार ने एसिड हमलों की रोकथाम, अपराधियों को दंडित करने, पीड़ितों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास के लिए एक व्यापक कानूनी, संस्थागत और नीतिगत ढांचा स्थापित किया है, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय से लागू किया जा रहा है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत "पुलिस" और "सार्वजनिक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। तदनुसार, कानून व्यवस्था बनाए रखने, जांच करने, अभियोजन चलाने और नागरिकों की सुरक्षा, जिनमें एसिड हमलों के पीड़ित भी शामिल हैं, की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की है। राज्य सरकारें मौजूदा कानूनों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023, जिसने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया है, के तहत एसिड हमले को गंभीर अपराध के रूप में मान्यता दी गई है। बीएनएस की धारा 124(1) में एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ से गंभीर चोट पहुंचाने पर कम से कम दस वर्ष के कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुमार्ने का भी प्रावधान है जो पीड़ित के उपचार के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए उचित और तर्कसंगत होना चाहिए। बीएनएस की धारा 124(2) में एसिड हमले के प्रयास को अपराध घोषित किया गया है और जुमार्ने के साथ पांच से सात वर्ष के कारावास का प्रावधान है, जिससे गंभीर चोट न लगने की स्थिति में भी अपराध को रोकने के लिए कड़ा दंड सुनिश्चित होता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 396 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के समन्वय से पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना तैयार करेगी, जिसके तहत अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट झेलने वाले और पुनर्वास की आवश्यकता वाले पीड़ित या उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। धारा में यह भी प्रावधान है कि देय क्षतिपूर्ति पीड़ित को जुमार्ने के भुगतान के अतिरिक्त होगी।